friend's ministry or by whatever other agency one does not know. The whole procedure is merely to delay even the most common sense treatment of the academic community in this country. Is this the policy of Government which is leading to all kinds of incidents in Delhi and elsewhere very rightly?

PROF. S. NURUL HASAN: It is not the policy of the Government to procrastinate. The Kothari Commission had only said that this revision may take place It has not made any specific recommendation regarding the revised scale for college and university teachers. There have been other demands by various teachers' associations and organisations regarding running grades. All these matters had to be taken into account because they were not visualised by the Kothari Commission. It was for this purpose that in June 1969 a committee was appointed by the UGC. Normally we had hoped that the report would be available within one year. But for certain unfortunate reasons even now the second part of the report is not available. But I am being told that it would be made available very soon.

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI: May I know whether, on receipt of the second part of the report, the Education Ministry will take immediate measures about revising the scales of Delhi University teachers?

PROF. S. NURUL HASAN: The report would be given urgent consideration by Government. But as he knows, the moment any decision involves expenditure, the Finance Ministry will have to be consulted. Therefore, it would take some time for Government to hold consultations and find them necessary funds. But I can assure the House that so far as I am concerned, I will take as urgent a step as is physically possible under the circumstances to have a decision taken on this report.

D.T.C. Buses in operation

*292 SHRI DALIP SINGH: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) the break-up of the total number of buses owned by the D.T.C.; the number of buses in operation and the number of such buses under repair;

(b) the total number of private buses requisitioned and/or taken on contract for operation in D.T.C. and the total amount paid to private owners since the setting up of the D.T.C; and

(c) whether D.T.C. is deriving any profit from private owned buses, if so, the amount thereof?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR): (a) to (c). The relevant facts and figures regarding buses owned, operated and hired by the D.T.C as on 28th February 1973 are given below:—

I	(i)	Total number of buses owned by D T. C .	1574
	(ii)	No. of private buses hired	189
	(iii)	Total No of DTC buses on road	1219
	(iv)	No. of DTC buses kept as stand-by for emergent requirements. . . .	8
	(v)	No. of DTC buses held up for inspection under the Motor Vehicles Act.	5
	(iv)	Total number of private buses on road .	182
	(vii)	Total number of DTC and private buses in operation	1414
II		D.T.C buses more than 8 years old . . .	400
III		D T.C. buses under major or minor repairs .	232
IV		Hire charges Paid to the Private Operators for the Period 3.11.71 to 31 1 72 .	Rs 186 52 Lakhs
V		Total revenue earned through the Private buses hired during the same period . . .	Rs 178 26 Lakhs

श्री दलीप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दिल्ली के देहाती इलाके में जो बसें चलती हैं उन में क्या यह ठीक है कि 95 प्रतिशत बसें पुरानी हैं ? उस के साथ साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि नई बसें जब डी टी सी के पास आएंगी तो क्या उन बसों को दिल्ली के देहाती इलाके में भी चलाएंगे या नहीं और नई बसें कब तक आएंगी ?

श्री राज बहादुर : मैंने कहा कि 1514 में से 400 बसें पुरानी हैं जो आठ साल से ज्यादा पुरानी हैं और जो अपनी लाइफ सर्व कर चुकी हैं । हो सकता है कि उन में से कुछ ज्यादा मिकदार में देहात में हों लेकिन हमारी कोशिश है कि देहात में पुरानी बसें ज्यादा न जांय, नई बसें जांय और जैसे ही हमारे पास नई बसें आएंगी हम नई बसें वहां चालू करेंगे ।

श्री दलीप सिंह : मंत्री महोदय ने कहा है कि प्राइवेट बसों से कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना नुकसान हुआ ? फायदा नहीं हुआ तो नुकसान तो हुआ ही होगा । कितना नुकसान हुआ ? और यह प्राइवेट बसें जो हैं जब डी टी सी में नई बसें आ जाएंगी तो इन को हटा देंगे या कुछ को बाकी रखेंगे ?

श्री राज बहादुर : हमारी कोशिश यह है कि जैसे ही हमारे पास नई बसें आएं हम प्राइवेट बसों को हटाएं । जहां तक नुकसान और फायदे का सवाल है मैंने पहले खुद बयान कर दिया था कि हम ने इन प्राइवेट बसों के जरिए से 1 करोड़ 78 लाख 26 हजार रुपये कमाए और जो हम को किराया देना पड़ा प्राइवेट बसों को वह है 1 करोड़ 86 लाख 52 हजार रुपये । करीब 8 लाख का हमें घाटा हुआ ।

SHRI S. M. BANERJEE: In view of the fact that Delhi has expanded beyond expectations the number of buses required has also increased. Therefore, will the government take over the entire transport service in Delhi instead of leaving it partly in private hands, so that there will be no problem?

SHRI RAJ BAHADUR: Even now it is not in private hands. Only the DTC is hiring private buses and paying hire charges.

SHRI S. M. BANERJEE: Instead of taking the private vehicles on hire why do you not nationalise them?

SHRI RAJ BAHADUR: There are all types of private vehicles of different ages. I do not know whether it is the best proposition to buy them over Further, this question pertains to DTC buses in operation and not to nationalisation.

श्री शशि भूषण : दिल्ली की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ रही है और आप ने काफी नई बसों के लिए आर्डर्स भी दिए हैं । लेकिन टाटा कम्पनी ट्रक चूंकि बहुत ब्लैक में बिकता है इसलिए वह आप को देते नहीं और प्राइवेट बस बाडी मैन्युफैक्चरर्स के पास आप बस बनाने को भेजते हैं तो वह भी देर से बनाते हैं । मैं एक साधारण सा सवाल रखना चाहता हूं कि शक्तिमान ट्रक डिफेंस मिनिस्ट्री से ले कर आप बसें बनाकर चलाएं जिस में सवारियां खड़ी हो कर जा सकें, इस ढंग की साधारण सी सुविधा भी गवर्नमेंट कालोनीज में दे सकें तो आप को पचासों ट्रक्स मिल सकते हैं । क्या इस ढंग की कोई योजना आप बनाएंगे जिस से जो सरकारी कर्मचारी हैं उन को आने जाने में सुविधा हो ?

श्री राज बहादुर : चौथी पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत प्रथम तीन वर्षों में जब

कि 3 नवम्बर 1971 को हम ने डी टी सी को लिया 304 बसें नई ली गई थीं । उस के बाद हम दो वर्षों में 294 बसें और आ गई हैं और 432 का आर्डर दिया है । 719 नई बसों के आर्डर दिये गये हैं । लेकिन शक्तिमान ट्रक का क्या किया जा सकता है यह आप का सुझाव नया है, इस पर गौर किया जा सकता है ।

श्री टी० सोहन लाल: आज से 6–7 महीने पहले एक मीटिंग बुलाई गई थी इसी मामले पर और दिल्ली के कुछ खास खास आदमियों ने कुछ सुझाव दिए थे जिन के अंतर्गत दिल्ली पार्लियामेंट के मेम्बर भी थे तो मंत्री महोदय बताएंगे कि उन सुझावों के ऊपर भी चला गया या नहीं ?

दूसरे, उस वक्त प्राइवेट बसों के मामले मे जब यह सवाल चला कि प्राइवेट बसें खुद चलाने के अंदर इन को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तब यह सुझाव भी आया था कि क्यों न प्राइवेट बसों से कुछ मंथली ले कर उन को छूट दे दी जाय जिस से नुकसान न हो, तो इस पर कोई कार्यवाही की गई या नही ?

श्री राजबहादुर : मै माफी चाहता हू, मैं समझ नहीं पाया माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं भी नही समझ पाया ।

श्री टी० सोहन लाल : एक बार यह सुझाव दिया गया था कि प्राइवेट बसें जो चल रही हैं उन को इजाजत देते वक्त उन के ऊपर कर डाल दिया जाय, उन के ऊपर कुछ भार डाल दिया जाय जिस से कुछ मुनाफा हो लेकिन मुनाफा होने के स्थान पर नुकसान हो रहा है और प्रोइवेट बसों के मालिक मौजूद थे उस समय जो पैसा देना चाहते थे लेकिन समझ में नहीं आता कि उन से पैसा न ले कर यह नुकसान क्यो उठाया जा रहा है? . . . (*व्यवधान*) . . . . .

श्री शशि भूषण : वह मिनिस्टर बदल गए । वह बातचीत श्री ओम मेहता जी के साथ हुई थी ।

MR. SPEAKER: One Member has taken so much time. I am sorry I am not going to allow any room.

Study of Relay Cropping

*296. SHRI D D. DESAI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether adverse comments on relay cropping was made in the suicide note of Dr. Vinod Shah of the Indian Agricultural Research Institute, Pusa;

(b) whether Government have undertaken an independent study of the claims on behalf of relay cropping made by the Institute, and

(c) if so the level of success achieved in relay cropping in actual field conditions in different part of the country according to reports received by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) to (c). A statement is laid down the Table of the Sabha.

[*Placed in Library. See* No. LT-4153/73.]

SHRI D. D. DESAI: Will the hon. Minister be pleased to state whether the Inquiry held by the Gajendragad-